कोटद्वार, गुरूवार
25 जुलाई 2024
वर्षः 46
अंकः 91 पृष्ठः 4
मूल्यः 2.00
RNI No.UTTHIN/2005/16338

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नरेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोन: 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

एक नजर

लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में भर्ती

नई दिल्ली , राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मंगलवार देर रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई, इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है और इसके साथ ही अब उनकी हालत स्थिर बताई गई है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। लालू प्रसाद यादव के साथ उनके परिवार के लोग अस्पताल में मौजूद हैं। बढ़ती उम्र के कारण लालू प्रसाद यादव पहले से ही कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहें हैं, उन्हें पहले से ही कई गंभीर बीमारियां है। इस वजह से अब वे राजनीति में भी इतने ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आते। लालू प्रसाद यादव को लंबे समय से शुगर है साथ ही उनकी किडनी डेमेज भी हो गई थी। बता दें कि लालू प्रसाद यादव का कुछ समय पहले किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी डोनेट की थी।लालू यादव यादव की अस्पताल में भर्ती होने की तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब से आरजेडी के समर्थक और लालू यादव के प्रशंसक उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने लगे। इस बात की सबसे पहले जानकारी आरजेडी के नवनिर्वाचित सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के फेसबुक पोस्ट से हुई। सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि लालू यादव की तबीयत खराब है, जिसके चलते उनको एम्स में भर्ती कराया गया है।

चेक बाउंस के दोषी को तीन माह की सजा

काशीपुर। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय एसीजे की अदालत ने आरोपी को तीन माह के कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।महुआखेड़ागंज स्थित एनएक्ससी कंपनी कीटनाशक दवा का कारोबार करती है। वर्ष 2022 में ग्राम गंगेरू जिला शामली निवासी गोविंदा ने उसकी कंपनी से 1.68 लाख रुपये की दवाइयां खरीदी थीं। रकम के भुगतान की एवज में उसने कंपनी को इसी राशि का चेक दिया था। कंपनी के डायरेक्टन बैनेट मैसी ने यह चेक अपने खाते में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। इसपर मैसी ने अपने अधिवक्ता रहमत अली खां के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय एसीजे की अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी गोविंदा को 138 एनआई एक्ट के तहत दोषी पाया। द्वितीय एसीजे चेतन सिंह गौतम की अदालत ने आरोपी गोविंदा को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसपर दो लाख रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का कारावास और भोगना होगा।

चार दिन से बंद बोसान मार्ग एक घंटे खुलने के बाद फिर बंद

विकासनगर। बीती रात बारिश के चलते बुधवार को जौनसार बावर क्षेत्र की नौ सड़कों पर यातायात ठप रहा। सड़कें बंद होने से स्थानीय लोगो को रोजाना दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। उधर, बोसान मोटर मार्ग एक घंटे खुलने के बाद दोबारा बंद हो गया। इससे क्षेत्र के लोग चौथे दिन भी परेशान रहे। चकराता, सहिया और कालसी क्षेत्र में बारिश के चलते रोजाना मुख्य और सम्पर्क मार्ग बंद हो रहे हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कालसी के अंतर्गत आने वाला बोसान मोटर मार्ग एक बार खुलने के बाद फिर बंद हो गया। चकराता के अंतर्गत आने वाले टुंगरा संपर्क मार्ग, रावना–पुरोड़ी मोटर मार्ग दो जगह, कोटी–कनासर–रजाणु पिंगवा मोटर मार्ग दो जगह, अणु–चिल्हाड मोटर मार्ग दो जगह, सहिया के अंतर्गत आने वाले काहा–नेहरा–पुनहा मोटर मार्ग दो जगह, पीएमजीएसवाई कालसी का कोठा–बैंड–पंजिया मोटर मार्ग दो जगह, गडोल–सकरोल मोटर मार्ग तीन जगह, परिहार संपर्क मार्ग दो जगह मलबा आने से यातायात के लिए बाधित रहा। मार्ग बंद हो जाने से किसानों को अपनी टमाटर, गोभी आदि की नगदी फसलों को मंडी तक पहुंचाने में परेशानी हुई। साथ ही जरूरी कार्य से शहर, तहसील और ब्लाक मुख्यालय जाने वाले ग्रामीणों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन

● मुख्यमंत्री ने की केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा

जयन्त प्रतिनिधि।रूद्रप्रयाग : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को बाबा केदारनाथ के दर्शनों को श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं विश्व कल्याण की कामना की। इसके बाद उन्होंने केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का की समीक्षा की।

एक दिवसीय दौरे पर बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों को पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे, आईजी पुलिस गढ़वाल करन सिंह नगन्याल, जिलाधिकारी डॉ. सौरभ गहरवार एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. विशाखा वीआईपी हैलीपैड पर स्वागत किया। ड्यूटी पर मौजूद सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अभिनंदन करने के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ पुरोहित समाज एवं मुख्य पुजारी से मिले।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना एवं रुद्राभिषेक कर संपूर्ण विश्व एवं मानवता के कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के सतत विकास के लिए भी बाबा केदार से आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने धाम के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद तीर्थ पुरोहितों के साथ धाम में चल रहे निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों के संबंध में चर्चा कर विकास कार्यों के सुझाव मांगे। उन्होंने केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण एवं पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने एवं गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समयबद्धता के साथ सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीकेटीसी योगेन्द्र सिंह, प्रभारी कार्यकारी अधिकारी आरसी तिवारी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल, अनूप सेमवाल, केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, विनोद शुक्ला, किशन बगवाड़ी, उमेश पोस्ती, केशव तिवारी, दिनेश बगवाड़ी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी एवं तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे।

ऋषिकेश में कूड़ा प्लांट बनाने को पेड़ काटने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

नैनीताल। हाईकोर्ट ने गुमानीवाला ऋषिकेश के आबादी क्षेत्र में लगाए जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। बीते मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्लांट की जद में आ रहे 134 पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार, ऋषिकेश निवासी समाजसेवी आशुतोष शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम द्वारा सरकारी धन को ठिकाना लगाने के लिए आनन–फानन में गुमानीवाला में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने की अनुमति दे दी गई है। जिस क्षेत्र में यह प्लांट लगाया जा रहा है वह आबादी वाला क्षेत्र है। इस प्लांट में पांच शहरों के कूड़े का निस्तारण किया जाना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नियमावली के अनुसार यह प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर लगाया जाना था। लेकिन नगर निगम ने इसे आबादी क्षेत्र में लगाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति सुप्रीम कोर्ट के 2019 के आदेश के खिलाफ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि ऐसे प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर स्थापित किए जाएं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने शपथ पत्र में नगर निगम के उस पत्र को कोर्ट के सामने रखा जिसमें कहा गया कि इस प्लांट की जद में 134 पेड़ आ रहे हैं, उन्हें काटने की अनुमति दी जाए।

जम्मू–कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़

एक आतंकी ढेर, एक जवान घायल

श्रीनगर , जम्मू–कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच रात से मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर के बीच सुरक्षाबलों के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल है। बता दें कि सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच यह मुठभेड़ जम्मू–कश्मीर के कुपवाड़ा की लोलाब घाटी के त्रिमुखा टॉप पर जारी है। सुरक्षाबलों ने आतंकियों को उस समय घेर लिया जब वह वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जंगल में भागने की कोशिश कर रहे थे।

एक दिन पहले ही 23 जुलाई को पुंछ के बट्टल सेक्टर में सुरक्षाबलों ने आतंकियों को बैकफुट पर ला दिया था। हालांकि, भारी गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल हो गया था, जो इलाज के दौरान शहीद हो गया। सेना के मुताबिक, जवान अलर्ट थे। हाल ही में 17 जुलाई को भी जम्मू–कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दो आतंकी ढेर हो गए थे। एनकाउंटर नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर के नजदीक रुह्ष्ट के पास हुआ था। इससे पहले डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में मुठभेड़ होने की बात सामने आई थी। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हुआ था।

राहुल गांधी ने संसद में बुलाए किसान, एंट्री नहीं मिल पा रही थी तो भड़क गए

नई दिल्ली ,बजट को लेकर संसद में विपक्षी पार्टियों की तरफ से खूब हंगामा किया जा रहा है। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कई किसान नेताओं को मिलने के लिए संसद में बुला लिया। बुधवार को संसद भवन पहुंचे इन किसान नेताओं को एंट्री नहीं मिली तो राहुल गांधी भडक़ गए। इस मौके राहुल गांधी ने कहा कि हमने इन लोगों को मुलाकात के लिए बुलाया था। लेकिन ये लोग संसद में उन्हें आने नहीं दे रहे हैं। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वे किसान हैं और उन्हें सरकार अंदर नहीं देखना चाहती। वहीं राहुल गांधी के ऐतराज के बाद उन्हें एंट्री मिल गई। अब किसान नेताओं से राहुल गांधी संसद भवन के अपने उस दफ्तर में मिल सकेंगे, जो उन्हें नेता विपक्ष के तौर पर मिला है। किसान नेताओं को एंट्री न मिलने के आरोपों पर मीडिया ने पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि यह बात तो आपको नरेंद्र मोदी ही बता पाएंगे। राहुल गांधी ने अपने ही अंदाज में कहा कि इन लोगों को शायद इसलिए अंदर नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि ये किसान हैं। वहीं अखिलेश यादव ने बजट में किसानों का ध्यान न रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम तो किसानों के लिए बजट मांग रहे थे, लेकिन ये उन लोगों के लिए पैकेज ला रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर यूपी को कुछ क्यों नहीं मिला। यदि आप बिहार के लिए पैकेज दे रहे हैं और बाढ़ से राहत दिलाना चाहते हैं तो पहले नेपाल से बात करनी होगी और यूपी में बाढ़ कम करनी होगी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ आनी बंद हो जाए तो फिर बिहार में भी नहीं आएगी।

आम बजट के खिलाफ इंडिया अलायंस के नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया है। विपक्षी दलों ने कहा कि इस बजट में सिर्फ दो राज्यों का ही ध्यान रखा गया है। अन्य राज्यों के साथ यह भेदभाव जैसी स्थिति है। राहुल गांधी ने कहा कि यह बजट तो संघीय ढांचे के खिलाफ है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव और टीएमसी के नेताओं ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि अब यह सरकार ऐसा बजट लाई है कि बस कुर्सी बची रहे। संजय राउत ने कहा कि अब तक सिर्फ गुजरात ही ख्याल रखा जाता था।

हृदय गति रुकने से ट्रक चालक की मौत

हल्द्वानी। बैजनाथ पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रक चालक की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बागेश्वर भेज दिया है। मंगलवार की रात हल्द्वानी निवानी निवासी काफिल अहमद उम्र 28 वर्ष गरुड़ से हल्द्वानी की ओर ट्रक ले जा रहा था। तभी टीटबाजार के पास अचानक उसकी तबियत खराब हो गई। उसके साथी उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ लाए। जहां चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया। उसके साथी उसे हल्द्वानी दिखाने की बात कहकर अस्पताल से चले गए। वह ट्रक चलाकर जाने लगा, लेकिन फिर उसकी तबियत खराब हो गई। उसके साथी उसे फिर अस्पताल लाए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही बैजनाथ के थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नगरकोटी दलबल के साथ अस्पताल पहुंचे और शव कब्जे में लिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए बागेश्वर भेज दिया है। बैजनाथ के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. वीके गुप्ता ने बताया कि चालक के दूसरी बार अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी।

आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करने वाला बजट : महाराज

कैबिनेट मंत्री बोले मोदी सरकार का बजट विकसित भारत के लक्ष्य को साधने वाला है

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के 48.21 लाख करोड़ रुपए के आम बजट को विकसित भारत के लक्ष्य को साधने, नये अवसरों को सृजित करने और उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की चिंता करने वाला बजट बताया है।

प्रदेश के पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, संस्कृति एवं जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के 48.21 लाख करोड़ रुपए के आम बजट को विकसित भारत के लक्ष्य को साधने, नये अवसरों को सृजित करने और उत्तराखंड में आये दिन आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करने वाला बजट बताते हुए कहा कि यह बजट 2027 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

यह बजट वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ अगले 5 वर्षों में भावी भारत की प्रगति की एक झलक भी दिखाता है। यह बजट शिक्षा, रोजगार युवाओं के कौशल विकास, स्वास्थ्य, शहरी एवं ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, युवाओं, उद्योगों और किसानों की समृद्धि के साथ-साथ देश की सुरक्षा की चिंता करने वाला बजट है। श्री महाराज ने कहा कि मोदी सरकार का यह बजट देश में नवाचार, शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के अलावा देश के करोड़ों युवाओं के सपनों को इंटर्नशिप का अवसर देकर उनका सपना साकार करने वाला बजट है।

उन्होंने कहा कि इस बजट में उत्तराखंड को पिछले वर्ष आपदाओं से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए विशेष सहायता पैकेज देने की घोषणा की गई है। जिसके तहत इस बजट में 86 करोड़ की प्रारंभिक धनराशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

इस बार केंद्रीय बजट से हमें 2,217 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। प्रदेश में 475 गांव और बसावटों तक सड़क पहुंचाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। 250 से अधिक आबादी वाले गांव योजना के तहत सड़कों से जुड़ेंगे। सरकार के बजट से राज्य में पंचायत का सशक्तिकरण होने के साथ-साथ सड़कों का भी विस्तार होगा।

बजट को लेकर सदन के बाहर और अंदर विपक्ष का हंगामा

● विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया,बजट को बताया भेदभावपूर्ण

नई दिल्ली , 23 जुलाई को वित् मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को इंडिया गठबंधन ने कुर्सी बचाओ बजट और भेदभावपूर्ण बजट बताया है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा करते हुए नारेबाजी की,विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया।संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया. इसमें सोनिया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी शामिल हुए। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा मोदी सरकार का ये बजट भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है।इस बजट में कई राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है।इसी अन्याय के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।हमारी ये लड़ाई सडक़ से संसद तक जारी रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा, यह बजट सिर्फ अपने सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए है... उन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समर्थन मूल्य किसान को ना देकर गठबंधन के साथियों को दे रहे हैं...उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए थे, क्या मिला उत्तर प्रदेश को? डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ लखनऊका लाभ लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही है या लखनऊवालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है... विकास बिहार जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ रहे हैं? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? आप पहले उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाढ़ रोके तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, बजट देश का होता है, यह देश का बजट नहीं है। बजट सरकार बचाने के लिए नहीं होता है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा, हम बस इतना चाहते हैं कि वे (केंद्र) सच बोलें और देश के युवाओं को गुमराह न करें...वे नौकरियां कैसे पैदा करेंगे? उन्होंने राज्यों को भी गुमराह किया है। यहां तक कि बिहार को भी गुमराह किया गया है, राज्य को कुछ नहीं दिया गया है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, ...ये कमाल का बजट इजात किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ कर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया और अपने राज्य की लगभग सारी सीट दे दी उन राज्यों को इस बजट में क्या मिला? जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया, या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है उन पर सब कुछ लुटा दिया गया।

सिस्टम पर सवाल उठाने को लेकर राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का पलटवार

नई दिल्ली , संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए नीट पेपर लीक मामले पर बयान दिया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। किरेन रिजिजू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पेपर लीक में जो भी शामिल हैं, उसे सजा मिलेगी। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संसद से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो भी कहा वो बहुत गलत था। जो छात्र या जो भी लोग पेपर लीक में शामिल हैं, या किसी ने पेपर लीक करने की कोशिश की है, या कहीं भी कोई दोषी या लिंक पाया गया, उस पर अलग से कार्रवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा है कि पूरा सिस्टम ही बिक चुका है। रिजिजू ने कहा कि इसके लिए राहुल गांधी को सदन से माफी मांगनी चाहिए। हमारे देश में कितने अच्छे–अच्छे लोग परीक्षा देकर, आज अच्छे पदों पर काम कर देश की सेवा कर रहे हैं। अगर एक दो लोग गलत हो जाते हैं, दो चार लोग दोषी पाये जाते हैं तो पूरे सिस्टम को दोष देना गलत है। सदन में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कोई भी खरीद सकता है।

कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस मुस्तैद, कई मार्ग परिवर्तित

नोएडा ,कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस के आला अधिकारी तैयारियों का निरीक्षण करने लगातार कांवड़ मार्ग और अन्य जगहों पर पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद दोनों जगह पर डाइवर्जन लागू किया गया है।नोएडा में भी कांवड़ यात्रा मार्ग का जॉइंट सीपी के साथ अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगा दी गई है। नोएडा के ज्वाइंट सीपी ने दूसरे स्टेट के पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत करके कांवड़ यात्रा के लिए समन्वय बनाया है।

नोएडा में जॉइंट सीपी के साथ बम स्क्वायड, डॉग स्क्वाड और अन्य फोर्स ने भी कांवड़ यात्रा मार्ग की चेकिंग की है। वहीं गाजियाबाद में भी पुलिस ने भारी वाहनों के बाद हल्के वाहनों के लिए भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। जिसके मुताबिक कई ऐसे मार्ग है जहां पर 27 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक प्राइवेट वाहनों का भी जाना पूरी तरीके से बंद रहेगा और साथ ही साथ वहां चलने वाले ऑटो रिक्शा को भी इन मार्गों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कई ऐसे मार्ग है जहां पर 29 जुलाई की रात 12 बजे से पूरी तरीके से सभी वाहनों का आवागमन बंद हो जाएगा।

किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है : सीतारमण

नई दिल्ली , वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट आवंटन में राज्यों के साथ भेदभाव किये जाने के विपक्ष विशेषकर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुये बुधवार को कहा कि इसमें किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है और बजट भाषण में सभी राज्यों का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन बजट दस्तावेजों में सभी राज्यों के आवंटन का उल्लेख होता है। सीतारमण ने संवाददाताओं से अनौपचारिक चर्चा में इस संबंध में पूछे जाने पर कांग्रेस को चुनौती देते हुये कहा कि देश में सबसे अधिक बजट पेश करने वाली पार्टी अपने पूर्ववर्ती वित्त मंत्रियों के बजट भाषण को पढक़र देखे कि क्या उसमें सभी राज्यों के नाम का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर बजट को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने और गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुये कहा कि बजट को लेकर राज्यसभा में सदन के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने जो आज किया है वह उनके लंबे राजनीतिक जीवन को देखते हुये उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में नाम का उल्लेख हो या नहीं हो, लेकिन बजट दस्तावेज में राज्यवार आवंटन का उल्लेख होता ही है। उन्होंने कहा कि बजट दस्तावेज में एक–एक रुपया का हिसाब होता है और कहां से आया तथा कहां गया का विस्तार से जिक्र होता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लिए अभी डेढ़ महीने पहले ही प्रधानमंत्री ने 26 हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरूआत की है जिससे करीब चार लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ का कहर, गढ़चिरौली में डूबे कई गांव

गढ़चिरौली , महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं। बाढ़ के चलते करीब 15 गांव पानी में डूब गए हैं। आवागमन में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।गढ़चिरौली में भारी बारिश की वजह से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बाढ़ का पानी कई गांवों के अंदर तक घुस गया है। इससे ग्रामीणों को खाने–पीने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं, प्रशासन की ओर से बाढ़ से निपटने के लिए खास इंतजाम किए हैं। बाढ़ के हालातों के चलते एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मार्गों को बंद कर दिया गया है। जिससे लोगों को आने–जाने में परेशानी हो रही है। गुजरात के कच्छ में भी बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण अवड़ासा स्थित संघाना नदी में बाढ़ आ गई। इससे बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। बाढ़ की चपेट में आने से करीब 15 गायें नदी में बह गईं। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं।

बिहार विधानसभा में आरक्षण पर विपक्ष के हंगामे के बीच भड़के नीतीश कुमार

पटना , बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भी विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के सदस्य आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे।हंगामा के बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े होकर कहा कि आपकी जो भी मांग है वह पहले ही पूरी हो चुकी है, इस पर हंगामा करने का कोई मतलब नहीं है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष नन्द किशोर यादव बार–बार उन्हें अपनी जगह पर जाकर बात कहने का आग्रह करते रहे। लेकिन, विपक्ष हंगामा करता रहा।

इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े होकर कहा कि सरकार ने पहले ही जातीय गणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया है। इस पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी सरकार द्वारा केंद्र सरकार को लिखा जा चुका है। इसके बाद इस मामले को लेकर हंगामे का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के बाद 94 लाख गरीबों की पहचान की गई है। उनके विकास के लिए सरकार ने दो–दो लाख रुपया देना शुरू कर दिया। इस दौरान, मुख्यमंत्री भडक़ते भी दिखे। उन्होंने एक महिला विधायक को कहा, महिला हो, कुछ जानती हो? कहां से आते हैं, इन लोगों ने कुछ किया है? 2005 के बाद महिला को हमने ही आगे बढ़ाया है।

संपादकीय

मानसून में बुरे हालात

उत्तराखंड में हर साल की तरह इस बार भी मानसून भारी गुजर रहा है और तमाम जनपदों से ऐसी खबरें आ रही है जहां लोग जल भराव के कारण परेशान है। पहाड़ों की तो अपनी विडंबना है कि वहां प्रकृति के कोप के आगे इंसान कुछ कर गुजरने की स्थिति में नहीं है लेकिन जब बात मैदानी क्षेत्र की होती है तो यहां मानसून से उपजने वाली अव्यवस्थाओं के लिए सीधे तौर पर सरकारी मशीनरी को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पहले से ही इस बार अच्छे मानसून की संभावनाएं जताई गई थी और लगातार हो रही बारिश भी यही जाता चुकी है कि मानसून के साथ–साथ आने वाले अगले मौसम भी कसौटियों पर खड़े उतरेंगे। परेशानी यह है कि मानसून के दौरान मैदानी क्षेत्रों में जल भराव से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। राजधानी देहरादून में ही जो हालात मानसून के दौरान उपज कर सामने आए हैं वह काफी चिंताजनक है। नदी–नालों का पानी सड़कों पर बड़ा है तो लोगों के घरों तक पानी ने अपनी पहुंच बना ली है। नगरों में बे हिसाब और अनियोजित विकास के कारण जल निकासी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कोई चर्चा ही करने को तैयार नहीं है और ना ही निर्माण संबंधी प्राधिकरण जल निकासी के मुद्दे को लेकर गंभीर नजर आते हैं। बड़े–बड़े निर्माण के बावजूद जल निकासी के विषय को किनारे कर दिया जाता है और ना ही प्राधिकरण के आला अधिकारी कभी निर्माण हो जाने के बाद जल निकासी के प्रबंधन पर जांच करते हैं। परिणाम सामने है और आज पूरा शहर जरा सी बारिश के बाद ही जलमग्न होने लगता है सड़के नदियों में बदल जाती हैं तो सफाई न होने के कारण नाले एवं नदियों का पानी रिहायशी क्षेत्र में घुसकर नागरिकों के लिए मुसीबत बन जाता है। मानसून से पूर्व दिखावे मात्र के लिए नालियों की सफाई की जाती है जिससे मानसून की बात तो छोड़िए बेमौसम की बारिश भी परेशानियां पैदा कर देती है। जब तक निर्माण एजेंसी जल निकासी की व्यवस्था को लेकर ठोस नीति नहीं बनाएगी तब तक ऐसे ही परिणाम हमारे सामने आएंगे। राजधानी समेत उत्तराखंड के सभी बड़े नगरों में अनियोजित विकास की गंगा बह रही है जिसमें नियम–कानून को तात्पर्य कर निर्माण कर दिए जाते हैं यह सोचे समझे बिना की पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा या फिर बरसात के समय जल निकासी की व्यवस्था क्या रहेगी? हर मानसून पर वर्तमान हालात ही देखने को मिलते हैं लेकिन सरकारी मशीनरी है कि सुधरने का नाम नहीं लेती।

एफएसएसएआई की विकास–यात्रा: वर्तमान और भविष्य

जे.पी. नड्डा

एनडीए शासन के दौरान दूसरी बार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनने के बाद, पिछले सप्ताह जब मैंने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का दौरा किया, तो मुझे 2014 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपने शुरुआती कार्यकाल का स्मरण हो आया। यह वह समय था जब एफएसएसएआई खुद को देश के खाद्य–सुरक्षा नियामक के रूप में स्थापित कर रहा था और उस पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के लिए खाद्य मानक और नीतियाँ तय करने की बड़ी ज़िम्मेदारी थी।

22 अगस्त 2016 को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के एक दशक पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जब मैंने पहली बार एफएसएसएआई टीम और विभिन्न हितधारकों से मुलाकात की, तो एफएसएसएआई का दृष्टिकोण स्पष्ट था। उनका लक्ष्य नीतियों को मज़बूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना तथा नागरिकों और खाद्य व्यवसायों के बीच सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तन को बढ़ावा देना था। इन पहलों को 'ईट राइट इंडिया मूवमेंट' के तहत खूबसूरती से एकीकृत किया गया है, जिसने सभी भारतीयों के लिए 'सुरक्षित, स्वस्थ और सतत' भोजन सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र 'संपूर्ण प्रणाली दृष्टिकोण' अपनाया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय और एफएसएसएआई हमारे देश के खाद्य–सुरक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। एक मज़बूत खाद्य–सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र केवल मज़बूत खाद्य–नीतियों और मानकों की नींव पर ही बनाया जा सकता है। यह जानकर खुशी होती है कि एफएसएसएआई के वैज्ञानिक पैनल और विशेषज्ञ समितियों में काफ़ी विस्तार हुआ है, जिसमें 88 संगठनों के 286 विशेषज्ञ शामिल हैं। इससे वैश्विक मानकों के अनुरूप मानकों और नीतियों के विकास की गति में उल्लेखनीय तेज़ी आई है।

एफएसएसएआई की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मिलेट के मानकों का सृजन है, जिन्हें 2023 में वैश्विक मिलेट (श्री अन्न) सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ये मानक कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के साथ साझा किए गए हैं, जिससे मिलेट के वैश्विक मानकों के विकास और भारत को एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और मानकों के विकास के साथ–साथ उनका प्रवर्तन और परीक्षण भी उतना ही आवश्यक है। पिछले आठ वर्षों में एफएसएसएआई के खाद्य–परीक्षण बुनियादी ढाँचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में, कैबिनेट ने राज्य खाद्य–परीक्षण प्रयोगशालाओं को मज़बूत करने के लिए ?482 करोड़ की मंजूरी दी। एफएसएसएआई ने "फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स" नाम से मोबाइल फूड लैब उपलब्ध कराकर दूरदराज़ के इलाकों तक पहुँचना शुरू कर दिया है।

सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और मानकों के विकास के साथ–साथ उनका प्रवर्तन और परीक्षण भी उतना ही आवश्यक है। पिछले आठ वर्षों में एफएसएसएआई के खाद्य–परीक्षण बुनियादी ढाँचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में, कैबिनेट ने राज्य खाद्य–परीक्षण प्रयोगशालाओं को मज़बूत करने के लिए ?482 करोड़ की मंजूरी दी। एफएसएसएआई ने "फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स" नाम से मोबाइल फूड लैब उपलब्ध कराकर दूरदराज़ के इलाकों तक पहुँचना शुरू कर दिया है। इन उपलब्धियों का उत्सव मनाते समय, हमें वैश्विक स्तर पर उभर रहे रुझानों, जैसे कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन, प्रयोगशाला में विकसित मांस आदि को भी स्वीकार करना चाहिए। एफएसएसएआई ने नई श्रेणियों, जैसे झ्र वीगन खाद्य पदार्थों, जैविक उत्पादों और आयुर्वेदिक आहार के लिए सक्रिय रूप से मानक विकसित किए हैं और यह खाद्य–सुरक्षा के उभरते रुझानों के अनुरूप निरंतर अनुकूलन कर रहा है।

इन उपलब्धियों का उत्सव मनाते समय, हमें वैश्विक स्तर पर उभर रहे रुझानों, जैसे कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन, प्रयोगशाला में विकसित मांस आदि को भी स्वीकार करना चाहिए। एफएसएसएआई ने नई श्रेणियों, जैसे झ्र वीगन खाद्य पदार्थों, जैविक उत्पादों और आयुर्वेदिक आहार के लिए सक्रिय रूप से मानक विकसित किए हैं और यह खाद्य–सुरक्षा के उभरते रुझानों के अनुरूप निरंतर अनुकूलन कर रहा है।

जैसे–जैसे वैश्विक खाद्य व्यापार का विस्तार हो रहा है, एफएसएसएआई कोडेक्स जैसे विभिन्न मंचों पर अंतरराष्ट्रीय नियामकों के साथ साझेदारी कर रहा है। इसका उद्देश्य बढ़ती आबादी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना है। एफएसएसएआई ने 2023 में दिल्ली में पहला वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया, जो खाद्य नियामकों के लिए उभरती खाद्य–सुरक्षा चुनौतियों के बारे में मिलने और विचार–विमर्श करने के लिए अपनी तरह का पहला सहयोगी मंच है।

एफएसएसएआई आने वाले महीनों में जीएफआरएस के दूसरे संस्करण के लिए तैयार है।

जब हम खाद्य–सुरक्षा पर बात करते हैं, तो उपभोक्ताओं और नागरिकों को साक्ष्य–आधारित जानकारी के माध्यम से विभिन्न खाद्य–सुरक्षा मुद्दों पर सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। तभी हमारा काम समग्रता से पूर्ण होगा। यहीं पर एफएसएसएआई का 'ईट राइट इंडिया' अभियान महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करके कि उपभोक्ताओं तक हर स्तर पर ज़रूरी जानकारी पहुँचे। इस परिवर्तनकारी कार्यक्रम को हमारे आउटरीच को मज़बूत करने और व्यावहारिक बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ाया जा रहा है, जो उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य विकल्पों की मांग करने के लिए सशक्त बनाता है और खाद्य व्यवसायों को बेहतर विकल्प प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है।

एफएसएसए, 2006 खाद्य–उत्पादों के लिए व्यापक मानकों को अनिवार्य बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे उपभोग के लिए सुरक्षित हैं। साथ ही, फूड–लेबलिंग के नियम उपभोक्ता को एक सूचित विकल्प बनाने में सशक्त करते हैं। विज्ञापन और दावों के लिए नीतियाँ यह भी सुनिश्चित करती हैं कि खाद्य व्यवसायों द्वारा खाद्य–उत्पादों पर कोई भ्रामक दावा नहीं किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने के लिए पर्याप्त तंत्र प्रदान करके उनके सामने आने वाली आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने में सहायक रहा है, विशेष रूप से भ्रामक विज्ञापनों, असुरक्षित या घटिया भोजन से संबंधित शिकायतों के सन्दर्भ में ।

खाद्य–सुरक्षा एक सामूहिक प्रयास है, और एफएसएसएआई विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह सम्पूर्ण सरकार और सम्पूर्ण प्रणाली दृष्टिकोण को अपना रहा है। एफएसएसएआई खाद्य–सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलों में उद्योग और अन्य हितधारकों को शामिल करके एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है।

एफएसएसएआई ने पिछले दस वर्षों में भारत की खाद्य–सुरक्षा स्थिति को महत्त्वपूर्ण रूप से बदला है। साथ ही, यह उभरती चुनौतियों का समाधान करने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। एफएसएसएआई का लक्ष्य अपनी प्रतिबद्धता और समग्र दृष्टिकोण से भारत को खाद्य–उत्पादन में ही नहीं, बल्कि खाद्य–सुरक्षा और स्थिरता में भी वैश्विक गुरु बनाना है।

जवानों की शहादत बड़ी चिंता का विषय

अजीत द्विवेदी

जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं। बाहरी लोगों पर हमले और हत्या के बाद अब सुरक्षा बलों पर हमले का सिलसिला तेज हो गया है। सिर्फ इस महीने में कम से कम सात जगह आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 12 जवान शहीद हुए हैं। डोडा के डेसा जंगल में सोमवार, 15 जुलाई को आतंकवादियों के हमले में सेना के एक कैप्टेन सहित पांच जवान शहीद हो गए। इससे पहले कुलगाम में दो जगहों पर मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों के दो जवान मारे गए।

इसके बाद कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने घात लगा कर हमला किया, जिसमें पांच जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों की ओर से बताया गया कि कठुआ में सेना की गाड़ी पर पहले ग्रेनेड से हमला हुआ और उसके बाद गोलियां चलाई गईं। यह घटना पिछले महीने रियासी में हुई घटना से मिलती जुलती थी, जिसमें आतंकवादियों ने यात्रियों से भरी एक बस के ड्राइवर को गोली मार दी, जिससे बस खाई में गिर गई और नौ लोगों की जान चली गई। माना जा रहा है कि आतंकवादी सेना की गाड़ी भी इसी तरह से खाई में गिराना चाहते थे ताकि अधिकतम नुकसान हो।

भारत सरकार का दावा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। एक आंकड़े के मुताबिक पांच अगस्त 2016 से चार अगस्त 2019 तक राज्य में नौ सौ आतंकवादी घटनाएं हुई थीं, जिनमें 290 जवान शहीद हुए थे और 191 नागरिकों की जान गई थी। लेकिन अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद अगले तीन साल में इसमें गिरावट आई। पांच अगस्त 2019 से चार अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकवादी घटनाएं हुईं, जिनमें 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिक मारे गए। लेकिन सवाल है कि क्या शांति काल में दूसरे किसी देश में एक सीमा पर इतने जवान शहीद होते हैं या इतने नागरिक मारे जाते हैं? जब पाकिस्तान के साथ युद्धविराम संधि लागू है और कोई लड़ाई नहीं चल रही है तो छद्म लड़ाई में इतने जवानों की शहादत और आम नागरिकों की मौत निश्चित रूप से बड़ी चिंता का कारण होना चाहिए।

दूसरा सवाल यह है कि पिछले कुछ समय से जब राज्य में शांति बहाली का दावा किया जा रहा था तो अचानक सैन्य बलों पर हमले की घटनाओं में क्यों तेजी आ गई? क्या राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होने और चुनाव की तैयारियों की वजह से ऐसा हो रहा है? गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मतदान के आंकड़े ऐतिहासिक थे। पिछले लगभग चार दशक में इतने ज्यादा लोगों ने वोट नहीं डाले थे। अब अगले दो महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को चुनी हुई सरकार मिलेगी। तभी सवाल है कि क्या आतंकवाद को भारत विरोधी नीति के तौर पर इस्तेमाल करने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान को इससे बेचैनी हो रही है कि क्यों जम्मू कश्मीर के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं?

यह संभव है कि पाकिस्तान और उसके समर्थन से फलने फूलने वाले आतंकवादी संगठन एक रणनीति के तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विफल करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हों। यह ध्यान रखने की जरुरत है कि पाकिस्तान ने लंबे समय से आतंकवाद को भारत विरोधी कूटनीति का एक हिस्सा बना रखा है और वह इसे छोड़ने वाला नहीं है। फर्क इतना है कि इसका रूप बदल रहा है। पुराने आतंकवादी संगठनों की जगह नए नाम के संगठन आ गए हैं। पुराने आतंकवादी सरगनाओं की जगह नए सरगना आ गए हैं। जैसे डोडा की ताजा घटना की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। इसका कारण यह है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की जांच से पाकिस्तान घबराया है और उसे किसी तरह से एफटीएफ की सूची से बाहर निकलना है।

इसलिए वह ये मैसेज बनवा रहा है कि उसने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है और कई समूहों को समाप्त कर दिया है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सारे आतंकवादी समूह अब भी नाम बदल कर सक्रिय हैं। भारत को इस साजिश को बेनकाब करने का प्रयास करना चाहिए ताकि पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बना रहा। एफएटीएफ का दबाव कम होगा तो पाकिस्तान की वित्तीय मुश्किलें कम होंगी और तब उसकी भारत विरोधी गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति का भी एक पहलू है। शरीफ बंधुओं ने सेना के साथ मिल कर सत्ता पर कब्जा कर लिया है और इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है, जिससे आवाम में नाराजगी है। इस नाराजगी को कम करने के लिए भी भारत विरोधी गतिविधियां तेज की गई हो सकती हैं।

जम्मू कश्मीर के बदलते सुरक्षा लैंडस्केप का एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत इस क्षेत्र में अपनी सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिए पूरी तरह से सैनिक व्यवस्था पर निर्भर है। सुरक्षा और शांति की जो तस्वीर दिखाई जा रही है वह लाखों सैनिकों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की वजह से है। भारत ने पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक वार्ता बंद कर रखी है। दोनों देशों के बीच कारोबार बंद है। खेल और फिल्म के जरिए होने वाली सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी बंद है। अगर दोनों देशों के आर्थिक हित जुड़े होते तो संभव है कि सुरक्षा के हालात इतने नहीं बिगड़ते। सेना के दम पर पूरे राज्य की सुरक्षा लंबे समय तक सुनिश्चित करना एक मुश्किल काम है।

इसी का एक दूसरा पहलू यह है कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय सेना कश्मीर घाटी में तैनात है। इसलिए वहां सुरक्षा बलों की मदद से काफी हद तक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। लेकिन अब आतंकवादी हमलों का निशाना जम्मू का इलाका है। कठुआ, राजौरी में लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जम्मू रेंज में भी सेना को उसी तरह का बंदोबस्त करना होगा, जैसा कश्मीर घाटी में किया गया है। यह सेना और सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाने वाला होगा।

एक समस्या यह भी है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत में मिलाने की चर्चा छेड़ दी। वोट के लिए भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा कि मोदी को जिताएं तो छह महीने में पीओके भारत का होगा। इससे पाकिस्तान रक्षात्मक हुआ है और चीन की भी चिंता बढ़ी है। हालांकि सामरिक रूप से यह संभव नहीं है कि भारत युद्ध करके पीओके को अपने में मिलाए लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं और कई केंद्रीय मंत्रियों के बयानों ने हालात बिगाड़ दिए। भारत की कूटनीति पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी बंद है या बहुत सीमित हो गई है। चीन के साथ कारोबार जरूर बढ़ रहा है लेकिन कूटनीति नहीं हो रही है। इस वजह से भी उत्तर में सीमा पर भारत पूरी तरह से सामरिक रणनीति पर निर्भर हो गया है।

पिछले अनेक बरसों से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है या उसकी आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक व्यवस्था ढह गई है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की व्यवस्था ढह नहीं गई है और ढहनी भी नहीं चाहिए क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न किसी देश की अगर राजनीतिक और सामरिक व्यवस्था ढहती है तो उसका कितना बड़ा खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसलिए वहां महंगाई बढ़ रही है या राजनीतिक झगड़े बहुत हैं या सेना ही मालिक है, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बरबाद कर दिया, जैसी भारतीय मीडिया में चलने वाली बहसों का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान जर्जर हालत में भी भारत के लिए बड़ी सुरक्षा चिंता पैदा किए हुए है। इसलिए सैन्य बल और सामरिक रणनीति के साथ साथ कूटनीति का इस्तेमाल बढ़ाने की जरुरत है।

धनुष की 50वीं फिल्म रायन को मिला ए कैटेगरी का सर्टिफिकेट, एडवांस बुकिंग ओपन

इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर साउथ सिनेमा से साउथ सुपरस्टार धनुष की एक्शन–थ्रिलर और मारकाट वाली फिल्म रायन रिलीज के लिए तैयार है. रायन को धनुष ने लिखा और खुद डायरेक्ट किया है. यह दूसरी बार है जब धनुष ने कोई फिल्म डायरेक्ट की है. रायन आगामी 26 जुलाई को रिलीज होने जा रही है. रिलीज से चार दिन पहले रायन की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. धनुष ने एक एक्स पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है. धनुष ने फिल्म रायन से अपना खून से लथपथ एक पोस्टर भी शेयर किया है. वहीं, बीते दिन रायन के प्री–रिलीज इवेंट में धनुष ने अपनी अगली फिल्म का भी एलान कर दिया है. इधर, फिल्म रायन को

सेंसर बोर्ड ने ए (वयस्क) कैटेगरी का सर्टिफिकेट थमाया है.

धनुष की एडवांस बुकिंग की बात करें तो सैकनिल्क के अनुसार, 22 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक फिल्म रायन ने तमिल भाषा में 665 शोज के लिए 34,233 टिकट सेल कर 48,22,604.41 रुपये कमा लिए हैं. वहीं, तेलुगू में फिल्म ने 133 शोज के लिए 3,920 टिकट सेल कर 6,88,975 रुपये बटोर लिए हैं. रायन ने ऑल इंडिया में 798 शोज के लिए 38,153 टिकट सेल किए हैं, जिससे उसकी कुल कमाई 55,11,5,79 रुपये हो गई है.

रायन तमिल के साथ–साथ हिंदी और तेलुगू में भी रिलीज होगी. धनुष की बतौर एक्टर रायन 50वीं फिल्म है. बीती 21 जुलाई की रात हैदराबाद में फिल्म रायन का प्री–रिलीज इवेंट हुआ. इस इवेंट में फिल्म की स्टारकास्ट धनुष, प्रकाश राज, नित्या मेनन, दुशारा विजयन, अपर्णा बाला मुरली, सुदीप किशन, कालीदास जयराम और एस जे सूर्या पहुंचे थे.

भारत के लड़के छठे और लड़कियां सातवें स्थान पर रही

ह्यूस्टन, यहां समाप्त हुई विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की टीम स्पर्धा में भारत के लड़के छठे और लड़कियां सातवें स्थान पर रहीं।पांचवें स्थान के लिए हुए मैच में लड़के इंग्लैंड से 1–2 से हार गए, जबकि लड़कियों ने सातवें स्थान के लिए हुए मुकाबले में न्यूजीलैंड को 2–1 से हरा दिया। दोनों मुकाबले निर्णायक मैच तक चले।

भारत परिणामः

पांचवें स्थान के लिए हुए मैच में लड़के इंग्लैंड से 1–2 से हार गए, जबकि लड़कियों ने सातवें स्थान के लिए हुए मुकाबले में न्यूजीलैंड को 2–1 से हरा दिया। दोनों मुकाबले निर्णायक मैच तक चले।

लड़कियांः भारत ने न्यूजीलैंड को 2–1 से हराया (शमीना रियाज एला लैश से 7–11, 12–10, 13–11, 4–11, 4–11 से हार गईं; निरुपमा दुबे ने एनाबेल जेम्मेल को 9–11, 11–6, 11–4, 8–11, 11–9 से हराया) ; उन्नति त्रिपाठी ने एला हिल को 11–4, 11–3, 11–6 से हराया)।

पेरिस ओलंपिक में मंडरा रहा डेंगू का बड़ा खतरा

फ्रांस, ओलंपिक गेम दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है. जिसमें दुनिया भर के एथलीट्स पार्टीसिपेट करने आते हैं. इस बार बार पेरिस में ओलंपिक गेम का आयोजन किया जा रहा है. लेकिन अब दूसरी तरफ साइंटिस्ट ने चिंता जताते हुए कहा है कि इतने सारे लोगों का एक जगह पर होने के कारण यह डेंगू बुखार के लिए सुपर–स्प्रेडर इवेंट बन सकता है. इसलिए गेम के दौरान खास सावधानी की जरूरत है.

फ्रांसीसी अधिकारियों ने डेंगू डिटेक्टिव की भर्ती की है जो पेरिस में जहां खेल आयोजित किए जाएंगे उसमें एशियाई टाइगर के मच्छर पर नजर रखा जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर से लोग यहां आएंगे. ओलंपिक के दौरान पेरिस में काभी ज्यादा भीड़भाड़ रहेगा. अगर मौसम की बात करें तो गर्मी और बरसात दोनों रहेंगे इसके कारण कीड़े और मच्छर पनपने के चांसेस बढ़ जाएंगे. यही वजह है कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं. जिस तरीके से ग्लोबल वॉर्मिंग बढ़ रही है उस हिसाब से देखें तो 13 यूरोपीय देशों में तेजी में डेंगू के मच्छर पनपे हैं.

डेंगू की बीमारी सिर्फ यूरोपीय मुद्दा नहीं है यह पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बनी हुई है. बीमारी की रोकथाम के लिए कई केंद्र रखे गए हैं. सीडीसी के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी मामले बढ़ रहे हैं.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डेंगू बुखार एक वायरल इंफेक्शन है जो संक्रमित मच्छर के काटने से इंसान में फैलता है. डेंगू, जिसे ब्रेक–बोन बुखार के रूप में भी जाना जाता है. उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अधिक आम है. गंभीर मामलों में डेंगू बुखार घातक हो सकता है.

बैड न्यूज ने वीकेंड़ बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, 30 करोड़ का आंकड़ा छूने से रह गई इंचभर दूर

कल्कि 2898 एडी, सरफिरा और इंडियन 2 जैसी फिल्मों के बीच विक्की कौशल की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बैड न्यूज इस शुक्रवर को रिलीज हुई थी. फिल्म का रिलीज से पहले काफी बज था और सिनेमाघरों में दस्तक देने के साथ ही फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया. इसी के साथ इसकी शानदार शुरुआत हुई और ये विक्की के करियर की सबसे बड़ी ओपनर भी बन गई. वहीं दूसरे दिन भी फिल्म ने डबल डिजीट में कमाई की. चलिए यहां जानते हैं ह्यबैड न्यूजह्ल ने तीसरे दिन यानी संडे को कितने करोड़ कमाए हैं?बैड न्यूज के ट्रेलर आने के बाद से ही उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती है. वहीं फिल्म के सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद इसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये फिल्म फैमिली ऑडियंस द्वारा खासी पसंद की जा रही है. ऐसे में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर कारोबार कर रही है. फिल्म की कमाई की बात करें तो बैड न्यूज ने ओपनिंग डे पर 8.3 करोड़ से खाता खोला था. दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में 23.49 फीसदी की तेजी आई और इसने 10.25 करोड़ की कमाई की. वहीं अब फिल्म की रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे की कमाई के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं.सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ह्यबैड न्यूजह्ल ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 11 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ ह्यबैड न्यूजह्ल का तीन दिनों का कुल कलेक्शन अब 29.55 करोड़ रुपये हो गया है.ह्यबैड न्यूजह्ल के ट्रेलर आने के बाद से ही उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती है. वहीं फिल्म के सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद इसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

डॉक्यूमेंट्री मॉडर्न मास्टर्स : एस.एस. राजामौली का ट्रेलर जारी

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर एस.एस राजामौली की बायोपिक डॉक्यूमेंट्री मॉडर्न मास्टरः एस.एस राजामौली का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. मॉडर्न मास्टरः एस.एस राजामौली की हाल ही में रिलीज डेट का एलान हुआ था. मॉडर्न मास्टरः एस.एस राजामौली आगामी 2 अगस्त को डिजिटल पर्दे के टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है. एस.एस राजामौली ने पिछली बार फिल्म आरआरआर बनाई थी. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा नोट छापे थे और इस फिल्म के सुपरहिट सॉन्ग नाटू–नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर मिला था.

पेरिस में अनुभवी ही नहीं भारत के युवा ओलंपियन भी हैं मेडल के दावेदार

नई दिल्ली, पेरिस ओलंपिक के करीब आने के साथ ही भारत में मेडल के दावेदारों की संख्या काफी बढ़ गई है। नीरज चोपड़ा, सात्विक–चिराग, मीराबाई चानू और निखत जरीन जैसे नाम तो आपने कई बार सुने होंगे, जो पहले से ही बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हैं और अपने–अपने खेल में मेडल के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन इस दल में ऐसे एथलीट भी हैं जो भारतीय खेल इतिहास में भविष्य की बड़ी ताकत हैं।

पेरिस में भारत के युवा ओलंपियन डेब्यू के लिए तैयार हैं। इस बार ओलंपिक में भारत की ओर से कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जो प्रभावशाली प्रदर्शन करके बड़े नामों से ज्यादा सुर्खियां बटोर

सकते हैं।117 सदस्यीय दल में 47 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हें एक या उससे अधिक ओलंपिक खेलने का अनुभव है। इनमें पुरुष हॉकी टीम समेत पांच पदक विजेता भी शामिल हैं जबकि 70 खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में शिरकत करने जा रहे हैं।चलिए एक नजर कुछ उन युवा ओलंपियन पर डालते हैं, जो पहली बार खेल के इस महाकुंभ में भाग ले रहे हैं लेकिन दिग्गजों को पछाड़ने का माद्दा रखते हैं।धिनिधि देसिंघु (तैराकी): 14 वर्षीय तैराक धिनिधि देसिंघु पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की सबसे युवा एथलीट के रूप में इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पिछले साल राष्ट्रीय खेलों और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। इस साल अच्छे प्रदर्शन के बाद वह शीर्ष रैंक वाली भारतीय महिला तैराक भी हैं। वह ओलंपिक में 200 मीटर फ्रीस्टाइल में भाग लेंगी।श्रीजा अकुला (टेबल टेनिस): टेबल टेनिस को फॉलो करने वाले लोगों के लिए यह एक जाना–पहचाना नाम है। अकुला पेरिस से टीटी में पहला ओलंपिक पदक लाने की शीर्ष संभावनाओं में से एक हैं। भारत की नंबर 1 रैंक वाली पैडलर के लिए ओलंपिक से पहले 8 महीने काफी शानदार रहे हैं।

एक नजर

सतपुली में आधार सेंटर खोलने की उठाई मांग

जयन्त प्रतिनिधि।

सतपुली : नगर पंचायत सतपुली में नियमित आधार सेंटर खोलने की मांग उठाई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सतपुली में आधार सेंटर न होने के कारण क्षेत्र की जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में सतपुली में आधार सेंटर जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए।

बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलबी पुष्पेंद्र राणा ने एसडीएम सतपुली अनिल चन्याल को ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र 5 ब्लॉकों का मुख्य केंद्र और यहां के ग्रामीणों का मुख्य बाजार भी है। आठ साल पहले सतपुली में आधार सेंटर बनाया गया था, लेकिन चुनावों के चलते जिसे बंद कर दिया गया है। स्थानीय निवासी भूपेंद्र सिंह, तेजपाल सिंह ने कहा कि आधार सेंटर नहीं होने से दूरस्थ इलाकों से आने वाले ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पूर्व की भांति आधार सेंटर खोलने की मांग की है।

लिखित आश्वसान पर पर्यावरण मित्रों की हड़ताल समाप्त

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : पर्यावरण मित्रों ने बुधवार को प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त कर दी है। हड़ताल समाप्त होने से शहरवासियों ने राहत की सांस ली है। पर्यावरण मित्रों ने कूड़ा उठाना शुरू कर दिया है।

शहर में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति की स्थापना की मांग को लेकर बीते सोमवार से उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ से जुड़े पर्यावरण मित्र हड़ताल पर चले गए थे, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था चौपट हो गई थी और जगह-जगह कूड़े के ढेर लग गए थे। संघ के जिलाध्यक्ष प्रवीन कुमार ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि मूर्ति निर्माण का लिखित आश्वासन मिलने पर हड़ताल समाप्त कर दी गई है। शहर में कूड़े को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति की स्थापना को लेकर एजेंसी चौक के पास जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

अभिभावक संघ के अध्यक्ष बनें दौलत कठैत

श्रीनगर गढ़वाल : रेनबो पब्लिक स्कूल चौरास में बुधवार को विद्यालय की प्रधानाचार्य डा. रेखा उनियाल की देखरेख में अभिभावक संघ का गठन किया गया। अभिभावक संघ के गठन पर अध्यक्ष दौलत कठैत, उपाध्यक्ष संगीता, सचिव प्रियंका अग्रवाल और सदस्य के रूप में डॉ. ज्ञान प्रकाश शर्मा, सुमन प्रकाश गैरोला, अभिषेक पुरवाल, शीतल घिल्डियाल, आरती खत्री, दुर्गी उनियाल को नियुक्त किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य डॉ. रेखा उनियाल ने नवयुक्त अभिभावक संघ के पदाधिकारियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उन्होंने पदाधिकारियों को विद्यालय से संबंधित गतिविधियां के बारे में जानकारी दी। (एजेंसी)

डीएवी की हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. पुष्पा खण्डूड़ी हुईं सेवानिवृत्त

देहरादून। डीएवी पीजी काजेल में हिंदी की विभागध्यक्ष व शिक्षक नेता प्रो. पुष्पा खण्डूड़ी बुधवार को सेवानिवृत्त हो गईं। उन्होंने छत्तीस सालों तक कालेज में अपनी सेवाएं दीं। उनको विदाई देने के लिए कालेज में एक समारोह का आयोजन किया गया था। जिसमें प्राचार्य डॉ. एसके सिंह सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा नेता व पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष विवेकानंद खंडूड़ी भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। समारोह के दौरान भावुक हुईं डा. पुष्पा ने कहा कि 19 दिसम्बर 1987 से वे डीएवी (पीजी) कालेज के हिन्दी विभाग में अध्यापन कार्य करा रही थीं। वे डीएवी शिक्षक संघ की अध्यक्ष भी रहीं और इस दौरान शिक्षक हितों की लड़ाई भी पुरजोर ढंग से लड़ी।

पेड़ों की लॉपिंग करना भूला विभाग, करंट फैलने का खतरा

कोटद्वार क्षेत्र में पेड़ों के बीच से गुजरती विद्युत तार

वर्षा से पूर्व क्षेत्र में नहीं की गई पेड़ों की लॉपिंग

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : वर्षा काल चल रहा है। लेकिन, अब तक क्षेत्र में ऊर्जा निगम की ओर से पेड़ों की लॉपिंग तक नहीं की गई है। नतीजा पड़ों के बीच से गुजर रही विद्युत तारों से करंट फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं, क्षेत्र में कई विद्युत पोल भी जर्जर स्थिति में खड़े हैं। लगातार शिकायत के बाद भी जिम्मेदार सिस्टम इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है।वर्षा काल से पूर्व उन टहनियों की लापिंग की जाती है, जिन्हें छूते हुए विद्युत तार गुजर रही हो। गत वर्ष तक ऊर्जा निगम बाजार के साथ ही अन्य स्थानों पर इसके लिए अभियान भी चलाता था। लेकिन, इस वर्ष ऊर्जा निगम अपनी इस जिम्मेदारी को भूल गया है। नतीजा, पेड़ों के बीच से गुजर रहा करंट कब आमजन की जिंदगी पर भारी पड़ जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। जबकि, भाबर क्षेत्र के कई वार्डों में महिलाएं पेड़ पर चढ़कर चारापत्ती भी काटती हैं। कहीं-कहीं तो घनी डालियों के बीच बिजली के तार दिखाई ही नहीं दे रहे।

लगातार होती रही है घटनाएं

शहर में छत के आसपास से गुजर रही विद्युत लाइन भी वर्षाकाल में खतरा बनी हुई है। कुछ वर्ष पूर्व आमपड़ाव मोहल्ले में बिजली केवी-33 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। दो वर्ष पूर्व कौड़िया वार्ड के सैनिक कालोनी में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक वृद्धा की झुलसने से मौत हो गई थी। इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में कई बार हो चुकी है। बावजूद सिस्टम विद्युत तार को घरों के आसपास से शिफ्ट करने की सुध नहीं ले रहा।

उद्यमिता विकास की दी जानकारी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : उद्यमिता विकास के लिए राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी यमकेश्वर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में उत्तराखंड राज्य से उच्च शिक्षा विभाग से 32 प्राध्यापकों ने प्रतिभाग किया।जनपद पौड़ी गढ़वाल से महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी यमकेश्वर से इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. उमेश त्यागी ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। बुधवार को वहां से लौटने के बाद उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में उद्यमिता विकास से संबंधित विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया तथा विभिन्न धरातलीय और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण आयोजित कर प्रतिभागियों को उद्यमिता विकास हेतु तैयार किया गया। कहा कि वे उत्तराखंड में युवाओं को उद्यमिता विकास हेतु प्रोत्साहित करेंगे, जिससे प्रदेश का युवा उद्यमिता में प्रवेश कर रोजगार के नवीन अवसर सृजित कर सके।

मोनिका बनी असिस्टेंट प्रोफेसर

असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन होने वाली छात्रा मोनिका

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार व राजकीय कन्या इंटर कालेज घमंडपुर की पूर्व छात्रा मोनिका का लोक सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए चयन हुआ है। मोनिका की इस सफलता पर उसके स्वजनों ने खुशी व्यक्त की है।

शैलशिल्पी विकास संगठन ने मोनिका की इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की। संगठन के अध्यक्ष विकास आर्य ने कहा कि मोनिका ने कड़ी मेहनत से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को हासिल किया गया है। एक बेटी की सफलता ने समाज की अन्य बेटियों का हौंसला बढ़ाया है। कहा कि मोनिका ने राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार से अर्थशास्त्र विषम से एमए करने के बाद नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वह अपने बैच में अर्थशास्त्र विषय की टापर भी रही है।

आधी क्षमता के साथ गैस गोदाम का लाइसेंस बहाल, उपभोक्ताओं को मिली राहत

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : जिला मुख्यालय पौड़ी में गढ़वाल मंडल विकास निगम के गैस गोदाम का लाइसेंस आधी क्षमता के साथ फिर से बहाल हो गया है। जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल गई है। गढ़वाल गैस सर्विस पौड़ी के प्रबंधक मुकेश डंगवाल ने बताया कि गैस गोदाम पौड़ी की लाइसेंस क्षमता 8 हजार किलो थी। जिसे 4 हजार किलो क्षमता का लाइसेंस प्रदान करते हुए फिर से बहाल कर दिया गया है। पाबौ और कोट हस्तांतरित गढ़वाल गैस सर्विस पौड़ी के सभी कनेक्शन वापस लाए जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सभी उपभोक्ताओं को मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह सुचारु रहेंगी।

बीते 4 जुलाई को उप विस्फोटक नियंत्रक अधिकारी देहरादून द्वारा मानकों का हवाला देते हुए पौड़ी के गैस गोदाम के लाइसेंस पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद उपभोक्ताओं में ऊहापोह की स्थिति बन गई थी। स्थानीय जनता व जन प्रतिनिधियों ने जहां गोदाम का संचालन यथावत रखे जाने की मांग की थी। वहीं डीएम पौड़ी ने तहसील प्रशासन को भूमि चयन के निर्देश दिए थे। पौड़ी में गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक एलपीजी गैस गोदाम है। गोदाम के संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण सितंबर 2023 से सितंबर 2028 तक उप विस्फोटक नियंत्रक अधिकारी देहरादून से हुआ था, लेकिन बीते 4 जुलाई को उक्त अधिकारी के कार्यालय से गढ़वाल गैस सर्विस पौड़ी कार्यालय को एक पत्र मिला। जिसमें उप विस्फोटक नियंत्रक अधिकारी देहरादून द्वारा सुरक्षा मानकों का हवाला देते हुए गोदाम के संचालन के लाइसेंस पर अंतरिम रुप से रोक लगाए जाने की जानकारी दी गई थी। जिसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्रशासन द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पाबौ व कोट में संचालित एजेंसियों के सहयोग से सेवा के सुचारु संचालन की व्यवस्था की थी। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन व शासन से गोदाम के यथावत संचालन की मांग की थी। डीएम पौड़ी ने शासन से पत्राचार करने के साथ ही तहसील पौड़ी प्रशासन को गोदाम निर्माण के लिए भूमि चयनित किए जाने के निर्देश दिए थे। तहसील प्रशासन ने पांच नाली भूमि चयनित कर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जिसमें मिट्टी की जांच सहित अन्य औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए थे।

विद्युत बिल बढ़ोत्तरी पर कांग्रेस ने जताया रोष, आंदोलन की चेतावनी

ऊर्जा निगम में अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देते कांग्रेसी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : बिजली बिलों में अतरिक्त सरचार्ज जोड़े जाने के खिलाफ कोटद्वार महानगर और यूथ कांग्रेस ने बुधवार को प्रदेश सरकार को घेरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल्द बिजली बिलों में बढ़ोतरी को वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कहा कि जनता की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ऊर्जा निगम की ओर से बिलों में अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है जिससे आमजन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। कहा कि निगम की ओर से बिजली बिलों में कभी फ्यूल चार्जेज तो कभी फिक्स चार्जेज सहित अन्य चार्जेज में वृद्धि की जा रही है। साथ ही उपभोक्ताओं से बिजली मीटर की सिक्योरिटी राशि भी दोबारा ली जा रही है। इस सब से आम जन का बिल दोगुना हो रहा है, जिससे जनता परेशान हैं। ज्ञापन में उपरोक्त सभी मुद्दों का निस्तारण करने की मांग उठाई गई है और ऐसा नहीं होने पर जनता के सहयोग से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन प्रेषित करने वालों में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय मित्तल, कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीन रावत, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय रावत, धीरेंद्र बिष्ट, बृजपाल सिंह नेगी, सुदर्शन रावत, गणेश नेगी, देवेंद्र सिंह नेगी, सुनील दत्त सेमवाल और ताजबर सिंह नेगी सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे।

विद्यार्थियों ने खेल-खेल में सीखी गणित के विधाएं

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : पब्लिक इण्टर कालेज सुरखेत में मनाए जा रहे शिक्षा सप्ताह के तहत विद्यार्थियों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने खेल-खेल में गणित के सूत्र भी सीखे।

प्रधानाचार्य पुष्कर सिंह नेगी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा सप्ताह का उद्देश्य विद्यार्थियों व शिक्षकों के बीच सहयोग और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है।

एनईपी-2020 के क्रियान्वयन तथा विगत चार वर्षों की उपलब्धियों को साझा करना है। विद्यालय में मनाए जा रहे शिक्षा सप्ताह के तीसरे दिन स्पोर्ट्स डे पर व्यायाम शिक्षक प्रमोद रावत, संजय कुमार, सतीश चन्द्र शाह, डा. तपेन्द्र बिष्ट, प्रमोद कुमार रमोला, दिनेश बिष्ट, प्रकाश कैंथोला, नीरज रमोला, विजेता गडोई के मार्गदर्शन में बालक और बालिका वर्ग की कबड्डी और रस्साकस्सी प्रतियोगिताओं के साथ ही संख्याओं के मैजिक बॉक्स द्वारा खेल-खेल में गणित सीखना जैसी विधाओं का आयोजन किया गया।

पब्लिक इंटर कॉलेज सुरखेत में आयोजित खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते विद्यार्थी

इससे पूर्व शिक्षा सप्ताह के प्रथम दिवस टीएलएम डे पर छात्र-छात्राओं ने जल संरक्षण, दूसरों की मदद करना जैसे विषयों पर पोस्टर बनाने के साथ ही हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण जैंसे विषयों पर कम लागत वाली शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार की।

द्वितीय दिवस निपुण/एफ. एल.एन. डे पर विद्यालय में आयोजित गोष्ठी में प्रधानाचार्य पुष्कर सिंह नेगी, शिक्षक संजय कुमार, प्रकाश कैंथोला ने निपुण भारत के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की जानकारी दी।

छात्रों को दी कानूनी जानकारी

श्रीनगर गढ़वाल : कोतवाली कीर्तिनगर पुलिस ने राइंका थापली में छात्र-छात्राओं को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी। कोतवाली प्रभारी कीर्तिनगर देवराज शर्मा ने छात्रों एवं शिक्षको कानूनों में बदलाव के बारे में बताया। कहा कि स्कूलों और अन्य जगहों पर भी लोगों को नए आपराधिक कानून 2023 के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। बताया कि भारतीय न्याय सहिंता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। आमजनता को कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं, संवाद, प्रचार-प्रसार शुरू किया गया है। (एजेंसी)

18 अगस्त होंगे व्यापार सभा के चुनाव

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : व्यापार सभा पौड़ी की नई कार्यकारिणी के चुनाव 18 अगस्त को होंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी कमल किशोर रावत ने व्यापार सभा पौड़ी का चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग के लिए वीरेंद्र सिंह रावत को चुनाव समंवयक और राम सिंह रावत, देवेंद्र सिंह रावत, निखिल रौथाण व संजय बडोनी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है।

बुधवार को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की पौड़ी इकाई का चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी कमल किशोर रावत ने बताया कि मतदाताओं का सत्यापन आगामी 1 अगस्त से शुरू होगा। बताया कि व्यापार सभा पौड़ी की कार्यकारिणी का तीन वर्षीय कार्यकाल पूरा हो गया है। व्यापारियों की सदस्यता अभियान भी पूरा हो चुका है।

सत्यापन के बाद मतदाता सूची जारी की जाएगी। बताया कि व्यापार सभा पौड़ी के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए 18 अगस्त को रामलीला मैदान में चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। 9 और 10 अगस्त को नामांकन होगा। नामांकन पत्रों की जांच 10 अगस्त नाम वापसी व प्रत्याशियों की अंतिम सूची 11 अगस्त को जारी होगी।

बताया कि 18 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना पूरी होने पर चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा।

तूणीसेरा गांव में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : तहसील धुमाकोट क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम तूणीसेरा में बीती मंगलवार सांय को बिजली का तार टूटने से गौशाला के निकट एक महिला और गाय करंट की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्व पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया।

ग्राम प्रधान कमंदा आनंद स्वरूप शर्मा ने बताया कि उक्त घटना की सूचना पर क्षेत्र के पटवारी, पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी नैनीडांडा भेज दिया। पट्टी बूंगी की पटवारी प्रियंका देवी ने बताया कि 65 वर्षीय सरोजनी देवी पत्नी प्रेमलाल ग्राम तूणीसेरा, ग्रामसभा कमंदा, पट्टी बूंगी, थाना तहसील धुमाकोट की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी नैनीडांडा लाया गया। जहां पर प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. आशुतोष त्रिपाठी व उनकी टीम द्वारा पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है।

विद्युत लाइन को दुरूस्त करने की मांग

जयन्त प्रतिनिधि।

सतपुली : तहसील क्षेत्र के नौगांव कमंदा तोक गांव के आवासीय भवनों के ऊपर गुजर रही विद्युत लाइन को दुरुस्त करने की मांग ग्रामीणों ने की है। ग्रामीणों का कहना है कि वह काफी समय से विद्युत लाइन की मरम्मत कराने की मांग कर रहे है, लेकिन उनकी मांग की अनदेखी की जा रही है। जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।

बुधवार को गामीण रविंद्र सिंह ने ऊर्जा निगम के अवर अभियंता को ज्ञापन देकर जल्द ही समस्या के हल करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि नौगांव कमंदा तोक गांव के आवासीय भवनों के ऊपर गुजर रही विद्युत लाइन कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में है। जो कभी भी टूटकर गिरने से हादसे का सबब बन सकती है। उन्होंने जल्द ही विद्युत लाइन के सुधारीकरण की मांग की है।

नहीं लगानी पड़ेगी देहरादून की दौड़, कोटद्वार में जल्द खुलेगा पासपोर्ट कार्यालय

विदेश मंत्री से मुलाकात करते गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने विदेश मंत्री डा. एस जयशंकर से मुलाकात करते हुए कोटद्वार व गोपेश्वर में पासपोर्ट कार्यालय खुलवाने की मांग की है। यदि कोटद्वार में जल्द पासपोर्ट कार्यालय खुल जाता है तो शहरवासियों को देहरादून की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। जिससे उनका धन व समय दोनों बचेगा।

बलूनी ने कहा कि इससे उत्तराखंड के छात्रों और नौजवानों को सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड के मेधावी छात्र और होनहार युवा वैश्विक स्तर पर दखल रखते हैं, पासपोर्ट कार्यालय खुलने से उन्हें यह सुविधा अपने क्षेत्र में ही प्राप्त होगी और उन्हें दूर के पासपोर्ट कार्यालय जाने से होने वाली असुविधा से राहत मिलेगी तथा समय व धन की बचत होगी। सांसद बलूनी ने कहा कि मोदी का तीसरा कार्यकाल आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने, उनकी अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने का है। सांसद बलूनी ने कहा कि विदेश मंत्री ने उनके अनुरोध को सकारात्मक रूप में लिया है और भौगोलिक विषमताओं को देखते हुए आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही मंत्रालय इस पर कार्रवाई करेगा।

नव प्रवेशित विद्यार्थियों का किया स्वागत

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : राजकीय महाविद्यालय कण्वघाटी में आयोजित कार्यक्रम में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

महाविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल के तत्वावधान में दीक्षारंभ छात्र प्रेरणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर डा. विजय कुमार अग्रवाल, डा. विनय देवलाल ने विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महाविद्यालय की संस्कृति, प्रथाओं व मूल्यों के विषय में अवगत भी करवाया। महाविद्यालय प्रबंधन की जानकारी देते हुए छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय की मेंटर मेंटी प्रणाली से जुड़ने वा छात्र द्वारा प्रगति व समस्याओं पर चर्चा करने को कहा। महाविद्यालय शास्ता मंडल संयोजक व वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. अरविंद सिंह ने नवप्रवेशित छात्र छात्राओं को महाविद्यालय से संबंधित नियम वा विनियमों की जानकारी दी। साथ ही छात्र सहायता योजनाओं व छात्रवृत्ति के विषय में विस्तृत जानकारी भी दी गई। महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी व सांस्कृतिक परिषद प्रभारी डॉ. गीता रावत शाह ने विद्यार्थियों को महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों व विभागीय कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित किया।

आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते विद्यार्थी

उत्तर रेलवे
निविदा सूचना
आज़ादी का अमृत महोत्सव

नं. 74-W/2/3/WA/Publication दिनांक : 22.07.2024

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियन्ता/प्रथम द्वारा ई टेन्डर जिनके बन्द होने की तिथि प्रत्येक निविदा के सामने अंकित है। निम्न टेन्डर संख्या के अन्तर्गत आमंत्रित किये जाते है जो उसी दिन 16:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। निविदा की कीमत तथा धरोहर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपोजिट रसीद आदि स्वीकार्य नहीं होंगे। टेन्डर से संबंधित अन्य जानकारी वैबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

टेन्डर संख्या दिनांक	81-DRM-MB-24-25 19.07.2024
कार्य का नाम	Provision of Drinking Water Facility and Augmentation to existing facilities at various Level Crossings Under Sr DEN/I/MB
निविदा प्रकार	Works
टेन्डर क्लोसिंग दिनांक/समय	20.08.2024 16:00
अनुमानित लागत	15,92,774.93
धरोहर राशि	31,900.00
बिडिंग स्टार्ट तिथि	06.08.2024
आफर की वैधता	60 दिन
कार्य पूर्ण करने की अवधि	06 माह

2244/24
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

एक नजर

उपनल कर्मचारियों ने की नियमितीकरण का लाभ दिए जाने की मांग

देहरादून। उपनल कर्मचारियों ने भी संविदा कर्मचारियों की तरह उन्हें भी नियमितीकरण का लाभ दिए जाने की मांग की। उपनल संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित किया जाए। अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि उपनल कर्मचारियों को जिस समय नियुक्ति पत्र दिया जाता है, उस समय स्पष्ट लिखा जाता है कि संविदा के आधार पर ही सेवा में लिया जा रहा है। शासन की ओर से भी अपने पत्र में संविदा पर रखने की स्वीकृति दी गई है। ऐसे में उपनल कर्मचारियों को 2013 की नियमावली में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है। विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी के लिए राज्य सरकार नियमावली बना रही है। इसमें उपनल कर्मचारियों को छोड़ा जा रहा है। उपनल कर्मचारी को भी राज्य में अपनी सेवाएं देते हुए 10 से 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सरकार नियमितीकरण नियमावली में उपनल कर्मचारियों को भी शामिल करे। कहा कि 22000 उपनल कर्मचारी है। इसमें 10 से 15 वर्ष के दायरे में सिर्फ चार से पांच हजार कर्मचारी ही आ रहे हैं। यदि राज्य सरकार इस नियमावली में उपनल कर्मचारियों को शामिल करती है, तो इन कर्मचारियों के नियमितीकरण का भी रास्ता खुल जाएगा।

कोटद्वार व गोपेश्वर में पासपोर्ट कार्यालय खोले जाएं

देहरादून। गढ़वाल सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय विदेश मंत्री डा.एस जयशंकर से मुलाकात कर कोटद्वार और गोपेश्वर में पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने का आग्रह किया। बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट कार्यालय न होने से युवाओं को देहरादून आना पड़ता है। कहा कि उत्तराखंड के मेधावी छात्र–छात्राएं और होनहार युवा वैश्विक स्तर पर दखल रखते हैं, पासपोर्ट कार्यालय खुलने से उन्हें यह सुविधा अपने क्षेत्र में ही प्राप्त होगी। इससे उन्हें दूर के पासपोर्ट कार्यालय जाने से होने वाली असुविधा से राहत तो मिलेगी साथ ही उनके समय व धन की भी बचत होगी।

उन्होंने ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने उनके आग्रह को सकारात्मक रूप में लिया है और भौगोलिक विषमताओं को देखते हुए आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही मंत्रालय इस पर कार्रवाई करेगा। उधर, बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने, उनकी अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने का है। कहा कि गढ़वाल के ऐतिहासिक विकास के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं।

विधायक पुंडीर ने किया राजावाला में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया

देहरादून। राजावाला में बनाए गए युद्ध स्मारक का सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर ने बुधवार को उद्घाटन किया। पूर्व सैनिक जनजाति समिति की पहल पर यहां युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया। उद्घाटन मौके पर बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। विधायक सहदेव पुंडीर ने कहा कि यह पूरा इलाका सैनिक बहुल है। यहां बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक निवास करते हैं। उनके बीच में युद्ध स्मारक न सिर्फ देश सेवा के प्रति उनके समर्पण की यादें ताजा करता है बल्कि नई पीढ़ी को भी यह युद्ध स्मारक सेना में जाकर देश सेवा करने की प्रेरणा देगा। उन्होंने कहा कि युद्ध स्मारक का निर्माण पूर्व सैनिकों के प्रयास से संभव हो पाया है। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य हेमलता नेगी, इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर एके सिंह, डॉ.धीर जोशी और गौरव सेनानी संगठन के महावीर सिंह नेगी के साथ ही पूर्व सैनिक जनजाति समिति के अध्यक्ष हनुमत सिंह रावत ने भी विचार रखे। संचालन शीशपाल सिंह रावत ने किया। कार्यक्रम में डीएस नेगी,बलवीर सिंह रावत समेत अन्य मौजूद रहे।

माधुरी बर्थवाल ने किया स्कूल में पौधारोपण

देहरादून। अकेशिया पब्लिक स्कूल नथनपुर में हरेला पर्व के तहत बुधवार को पौधारोपण किया गया। जिसमें पदमश्री माधुरी बर्थवाल,प्रबंधक मनमीत सिंह ढिल्लो,प्रधानाचार्या पूजा मारिया व उप प्रधानाचार्या ममता रावत ने पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान धाद संस्था कि ओर से सुशील पुरोहित,नीना रावत, सुरेंदर अमोली, महावीर सिंह रावत शुभम शर्मा, अर्चना ग्वाड़ी और सुदीप जुगरान सहित कई लोग मौजूद रहे।

भगवा को गांव-गांव तक रंगने वाले भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता अमर सिंह नहीं रहे

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : पौड़ी जनपद के विकासखंड कल्जीखाल के ग्राम आसूई के भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अमर सिंह का बुधवार को स्वर्गवास हो गया। उनकी उम्र 95 वर्ष थी। गत वर्ष उनकी पत्नी का निधन हो गया, जिस कारण वे मजबूरन गांव छोड़कर अपने बेटे के साथ फरीदाबाद चले गए उनके तीन बेटे एक बेटी है। बड़ा बेटा हिरेंद्र सिंह भारतीय सीमा सुरक्षा बल में उप निरीक्षक पद पर है। जबकि दो बेटे निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। उनके बड़े बेटे के दो बेटे भी भारतीय सेना में है।

करीब 23 वर्ष पहले, 2001 में तत्कालीन मुख्यमत्री भगत सिंह कोश्यारी, तत्कालीन शिक्षा मंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकासखंड कल्जीखाल में आयोजित कार्यक्रम पहुंचे तो कुछ दिन पहले ही अमर सिंह रावत को पैरालाइज अटैक पड़ा था, उस समय वह भाजपा मंडल अध्यक्ष थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी कई भाजपा नेताओं साथ में कल्जीखाल विखं के आसुई गांव पहुंचे, वह भी बांजखाल से करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर, क्योंकि भाजपा के शैशव काल से पार्टी को तन-मन से सींचने वाले अमर सिंह अस्वस्थ चल रहे थे। सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ते-चढ़ते कोश्यारी, त्रिवेंद्र और धामी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक विराजमान हो गए, किन्तु स्व. अमर सिंह शरीर से लाचार एक गुमनाम जिंदगी जीते रहे। हालात यहां तक पंहुच गए कि उन्हें अपने उस गांव, उस क्षेत्र तक को छोड़ने को मजबूर होना पड़ा, जहां आज भी उनकी पार्टी के प्रति समर्पण से उपजी फसल का मौजूदा दौर के भाजपा के नेता लुफ्त उठा रहे हैं। जीवन काल के अंतिम दो दशक तक अपने पैतृक गांव आसूई में रहे उनकी धर्मपत्नी की निधन होने पर उन्हें मजबूरन गांव छोड़कर जाना पढ़ा और एक वर्ष से अपने सबसे छोटे बेटे के पास फरीदाबाद में कल उन्होंने 95 वर्ष की अवस्था में उन्होंने देह त्याग दी। लेकिन उनके व उनके जैसे अनेक भाजपा के बुरे दौर के समर्पित कार्यकर्ता आज गुमनामी के अंधेरे में हैं या खामोशी से दुनिया से विदा हो रहे हैं। शोक व्यक्त करने वाले लोगों में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, विधायक राजकुमार पोरी, पूर्व विधायक मुकेश कोली जिला अध्यक्ष सुषमा रावत, ब्लॉक प्रमुख कल्जीखाल बीना राणा, मंडल अध्यक्ष अनिल नेगी, पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय पटवाल, सुरेंद्र प्रसाद खुगसाल, अशोक डुकलाण, पूर्व मंडल महामंत्री रविंद्र बिष्ट, मनोज नैथानी, राजगुरु ममगांई, पीताम्बर सिंह पटवाल, बीरेंद्र बिष्ट, चित्र सिंह रावत, पूर्व जिला उपाध्यक्ष दिनेश रावत आदि ने शोक व्यक्त किया।

कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ का केंद्रीय बजट को लेकर प्रदर्शन

देहरादून। महानगर कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ ने बुधवार को देहरादून में केंद्रीय बजट में उत्तराखंड और व्यापारियों की अनदेखी के विरोध में प्रदर्शन किया। डिस्पेंसरी रोड पर व्यापारी नेताओं ने नारेबाजी करने के साथ ही पुतला भी फूंका। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के व्यापारी नेताओं ने कहा कि यह बजट व्यापारी विरोधी है।

व्यापारियों को किसी तरह की राहत या सुविधा इस बजट में नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता घट रही है। सरकार हर तरफ से सिर्फ टैक्स वसूलना चाहती है। कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि आम लोगों की सुख सुविधाओं के बारे में बजट में कोई ध्यान नहीं रखा गया। व्यापारियों को लेकर भी बजट में कोई ऐलान बड़ा ऐलान नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के ट्रायल 25 व 27 जुलाई को

जयन्त प्रतिनिधि।

चमोली : मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के ट्रायल 25 व 27 जुलाई को खेल मैदान गोपेश्वर में लिए जाएंगे।

प्रभारी जिला क्रीडाधिकारी जयबीर रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री उददीयमान उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत जनपद के 08 से 14 आयु वर्ग के 150 बालक व 150 बालिकाओं का चयन निर्धारित बैटरी टेस्ट के 30 मी. फ्लाइंग स्टार्ट, 6 इनटू 10 शटल रन, 600 मी. दौड, स्टैंडिंग ब्राड जम्प, मेडिसीन बॉल थ्रो, फारवर्ड बैण्ड रीच दक्षता योग्यता के आधार पर किया जाना है। चयनित छात्र को प्रतिमाह 1500 की छात्रवृति प्रदान की जाती है। प्रतिभागी को गूगल प्ले स्टोर से एप्प डाउनलोड करते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। आयु की गणना 01 जुलाई 2024 को आधार मानकर की जाएगी और प्रतिभागी उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जनपद के प्रत्येक न्याय पंचायत, नगर पंचायत तथा नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अर्न्तगत प्रत्येक विद्यालय से 08 से 09, 09 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग में 2-2 बालक एवं बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद गोपेश्वर में अध्ययनरत बालक एवं बालिकाओं की प्रत्येक आयु वर्ग में चयन प्रक्रिया 25 एवं 27 जुलाई को स्पोर्टस स्टेडियम गोपेश्वर में आयोजित की जाएगी।

'केदारनाथ बचाओ' पदयात्रा पर निकली कांग्रेस

देहरादून। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति के निर्माण के विरोध में कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई ने प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के नेतृत्व में बुधवार को हरिद्वार में गंगा तट पर हर की पौड़ी से 'केदारनाथ बचाओ' पदयात्रा शुरू की। इस मौके पर, राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश पार्टी अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि हर की पौड़ी पर गंगा स्नान और पूजा–अर्चना करने के बाद कांग्रेस नेताओं ने केदारनाथ की ओर प्रस्थान किया।

दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति के प्रस्तावित निर्माण के विरोध में निकाली जा रही यह यात्रा गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए 14–16 दिनों में केदारनाथ धाम पहुंचेगी। इस मौके पर माहरा ने कहा कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है तथा उसके कहीं और प्रतीकात्मक निर्माण का विरोध किया जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के भी ऋषिकेश और अगस्तमुनि में इस यात्रा में भाग लेने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा था कि धाम और शंकराचार्यों के सम्मान को बचाने की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। रावत ने कहा था कि जब तक अपने इस घोर अपराध के लिए भाजपा माफी नहीं मांगेगी, तब तक केदारनाथ सम्मान बचाओ संघर्ष जारी रहना चाहिए।एक ट्रस्ट द्वारा दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति का निर्माण प्रस्तावित है जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था।

सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने की सीडीएस चौहान से मुलाकात की

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने दून के सेना अस्पताल में कार्डीलोजिस्ट एवं नेफ्रोलाजिस्ट की तैनाती करने का आग्रह किया। कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा कि अस्पताल में यह सुविधा न होने से पूर्व सैनिक व उनके परिवारों के समक्ष दिक्कत आती हैं।

कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के अन्य स्थानों पर भी सीएसडी कैंटीन और ईसीएचएस पालिक्लीनिक खोली जानी चाहिए। जोशी ने हल्द्वानी में वार विडो गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल के निर्माण तथा गढ़वाल में आर्मी स्कूल के निर्माण का भी अनुरोध किया। सीडीएस अनिल चौहान ने सभी बिंदुओं पर सेना की ओर से सकारात्मक आश्वासन देते हुए कार्यवाही करने का भरोसा दिया।

सितंबर 2024 से शुरू होगी श्री केदारनाथ धाम के द्वितीय चरण की यात्रा

जयन्त प्रतिनिधि।रूद्रप्रयाग : श्री केदारनाथ धाम की द्वितीय चरण की यात्रा को सुगम, सुव्यवस्थित एवं बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडेय ने जीएमवीएन गेस्ट हाउस गुप्तकाशी में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल एवं तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक कर केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। साथ ही उनके सुझाव भी लिए गए। आयोजित बैठक में सदस्य जिला पंचायत गुप्तकाशी गणेश तिवारी ने बताया कि गुप्तकाशी विश्वनाथ मार्ग में पानी निकासी के लिए उचित प्रबंधन नहीं है जिसमें उन्होंने नाली का निर्माण करने की मांग की। साथ ही उन्होंने वाहनों की पार्किंग हेतु उचित स्थान चिन्हित करने, श्रावण मास में गुप्तकाशी क्षेत्रांतर्गत मांस की बिक्री न करने, झूलते विद्युत लाइन के तारों को दुरस्त करने, अवैध तरीके से गैस की सप्लाई पर रोक लगाने, अस्पताल तक

रोड दुरस्त करने, आवारा पशुओं के गौसदन बनाने की मांग की। इस अवसर पर आयुक्त गढ़वाल मंडल ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से कहा कि सरकार व स्थानीय जिला प्रशासन चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित एवं बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर संबंधित समस्याओं का निराकरण संबंधित विभागों के माध्यम से निस्तारण 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए तथा जो शासन स्तर की समस्याओं को उनके माध्यम से शासन को उचित कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि आगामी केदारनाथ धाम की द्वितीय चरण की यात्रा को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों, होटल व्यवसायी, तीर्थ पुरोहितों के साथ आवश्यक बैठक की जाए।

एस.सी.ई.आर.टी के नवनिर्मित भवन का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण

सरकारी विद्यालयों में स्थापित 442 स्मार्ट क्लास रूम का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (एस.सी.ई.आर.टी) उत्तराखण्ड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर उन्होंने पं. दीन दयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वर्ष 2023 एवं 2024 हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले तीन-तीन स्कूलों, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सी.एस.आर. के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लास रूम का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण दिन है। शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लगन, समर्पण के बल पर उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं। ये पुरस्कार विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को आगे भी इसी मनोयोग से प्रयास करने के लिए प्रेरित करेंगे और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायक होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससीईआरटी भवन का निर्माण कार्य 02 साल में पूर्ण करने का शिक्षा विभाग को लक्ष्य दिया गया था। विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में 29 करोड़ 25 लाख की धनराशि से भव्य भवन का निर्माण किया गया है। एससीईआरटी भवन बनने से शैक्षिक विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान तथा राज्य के शिक्षा के तंत्र का सम्पूर्ण विकास किये जाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एस.सी.ई.आर.टी के भवन निर्माण के साथ ही इसकी गुणवत्ता भी अत्यधिक मायने रखती है। राज्य सरकार का स्पष्ट ध्येय है कि किसी भी तरह के निर्माण कार्य में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा सीएसआर के अंतर्गत बनी 442 स्मार्ट क्लास के शुरू होने से सरकारी विद्यालयों में पठन-पाठन की व्यवस्था में अधिक गुणवत्ता आएगी। राज्य सरकार राज्य के 840 विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना पर भी कार्य कर रही है। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के साथ ही जूते और बैग भी प्रदान किए जा रहे हैं। कक्षा 9 में प्रवेश करने वाली बालिकाओं के लिए साइकिल योजना एवं मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि राज्य का कोई भी विद्यार्थी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित न रहे और न ही उनकी पढ़ाई पर कोई असर पड़े। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक आधुनिक और व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। सभी को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के किसी भी छात्र-छात्राओं के जीवन में शिक्षा का अभाव नहीं होने देंगे। इस अवसर पर निदेशक एससीईआरटी श्रीमती वंदना गर्ब्याल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट, निदेशक प्राथमिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल एवं शिक्षा विभाग अधिकारी उपस्थित रहे।

शिक्षकों के ऑनलाइन व्यवस्था पर होंगे ट्रांसफर

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 30 अप्रैल को घोषित कर दिया था। जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु अच्छे संस्थानों में जाने का मौका मिलता है। आगामी शिक्षण सत्र के लिए रिजल्ट 20 अप्रैल तक घोषित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में अध्यापकों के ट्रांसफर में पारदर्शिता आई है। ट्रांसफर में काउंसलिंग व्यवस्था की शुरुआत की गई है। अब तक 5000 अध्यापकों के ट्रांसफर हो चुके हैं। एससीईआरटी और डायट को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है। आगामी वर्ष से टीचरों के ट्रांसफर भी ऑनलाइन व्यवस्था से होने लगेंगे।

प्रधानाचार्य और शिक्षक विद्यालयी शिक्षा के मजबूत स्तंभ

महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने शिक्षा विभाग को प्रेरणा और नई दिशा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एससीईआरटी का अपने भवन बनने से शैक्षिक विकास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में नये आयाम प्राप्त होंगे। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और विद्यार्थियों को शुभकामना भी दी। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि प्रधानाचार्य और शिक्षक विद्यालयी शिक्षा के मजबूत स्तंभ हैं।

जीईपी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने पद्मभूषण जोशी का किया सम्मान

देहरादून। उत्तराखंड में पर्यावरण सूचकांक लागू करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले पद्मभूषण डॉ.अनिल प्रकाश जोशी को जीईपी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। देहरादून में बुधवार को जुटे इन कार्यकर्ताओं ने वर्ष 2012 में न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड तक सात राज्यों में जीईपी लागू करने को लेकर साइकिल यात्रा निकाली थी।दून में जुटे इन पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वर्ष 2012 की साइकिल यात्रा की यादें भी ताजा कीं।

उन्होंने उत्तराखंड में पर्यावरण सूचकांक(जीईपी) लागू कराने में पद्मभूषण डॉ.अनिल प्रकाश जोशी की भूमिका को अहम करार दिया। उन्होंने डॉ.जोशी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया और उन्हें इस सफलता पर मिठाई खिलाई। साथ ही कहा कि अगले साल से पूरे प्रदेश में छह अप्रैल को जीईपी दिवस मनाया जाएगा।

संविदा पर नियुक्ति का जब नियम नहीं, तो किन्हें नियमित कर रही सरकार

देहरादून। विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने सरकार की संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेज कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। संगठन अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि राज्य में 2003 और 2004 में सरकार आदेश कर संविदा पर समूह ग और घ में नियुक्ति पर रोक लगाई थी। जब नियुक्ति ही नहीं हुई, तो किसे नियमित किया जाएगा। यदि राज्य में संविदा के आधार पर नियमानुसार कोई नियुक्त हुआ है, तो वो उपनल कर्मचारी हैं। विनोद कवि ने कहा कि 2003 और 2004 में कार्मिक विभाग के आदेश में साफ किया गया है कि बिना कैबिनेट की मंजूरी के किसी भी विभाग में कोई भी संविदा पर नियुक्ति नहीं होगी। इन 20 सालों में कैबिनेट ने किसी भी संविदा कर्मचारी की नियुक्ति का कोई आदेश नहीं किया। राज्य में सिर्फ उपनल से ही विधिवत प्रक्रिया अपना कर उपनल संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। इन्हीं उपनल संविदा कर्मचारियों को श्रम न्यायालय और हाईकोर्ट ने भी नियमितीकरण किए जाने का आदेश किया है। समान काम का समान वेतन देने की व्यवस्था की है। ऐसे में यदि सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जा रही है, तो उपनल कर्मचारियों को सवोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए। कहा कि उपनल कर्मचारियों को न मेडिकल की सुविधा मिल रही है। न ही उन्हें महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है।

पावन चिंतन धारा आश्रम के अध्यक्ष प्रो. पवन सिन्हा "गुरूजी" ने की राज्यपाल से भेंट

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से राजभवन में पावन चिंतन धारा आश्रम के अध्यक्ष प्रो. पवन सिन्हा ''गुरूजी'' ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने पावन चिंतन धारा के तहत लांच किए गए कार्यक्रम ''प्रोजेक्ट यूपीएससी'' के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पावन चिंतन धारा आश्रम के सहयोग से जल्द ही उत्तराखंड में प्रोजेक्ट यूपीएससी की शुरूआत की जाएगी।

उन्होंने बताया कि अभी यह प्रोजेक्ट सिक्किम राज्य में चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की समन्वयक सुरभी शर्मा ने बताया कि आश्रम द्वारा सिविल सेवाओं में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इस प्रोजेक्ट को लांच किया है। ऐसे बच्चे जो सिविल सेवाओं में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं लेकिन पारिवारिक, आर्थिक या अन्य परिस्थितियों से सिविल सेवाओं की तैयारी नही कर पाते उन्हें आश्रम द्वारा इस प्रोजेक्ट के तहत निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। आश्रम में विशेषज्ञ अध्यापकों सहित पूर्व सिविल सेवकों द्वारा बच्चों को टिप्स दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की विशेषता है कि इसमें समय प्रबंधन से लेकर दैनिक जीवनचर्या के प्रबंधन और बच्चों के व्यक्तित्व विकास को निखारने पर जोर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जल्द एक परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें संस्था द्वारा बच्चों को परामर्श के माध्यम से उनकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से यहां के युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे बच्चों को सिविल सेवाओं की तैयारी का मौका मिल पाएगा जो संसाधनों के अभाव में पीछे रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि यहां के युवाओं में विशेषकर बालिकाओं में असीमित प्रतिभाएं हैं वे संसाधनों के अभाव में अपना सपना पूरा करने से न रह जाय, उनके लिए यह प्रोजेक्ट मददगार साबित होगा।

उत्तराखंड को रेल बजट में 5 हजार 131 करोड़ का हुआ आवंटन

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री व इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी देहरादून) में आयोजित वर्चुअल प्रैस कांफ्रेस के माध्यम से उत्तराखंड के पत्रकारों को रेलवे बजट के संदर्भ में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार रेलवे को रिकॉर्ड 2 लाख 62 हजार का बजट में आवंटन किया गया है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के सुरक्षा के सवाल के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हिमालयी राज्य में रेलवे की जो सुरंगें बन रही हैं, वो बेहद एडवांस तकनीकि के साथ बन रही हैं।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना में 213 किमी. की सुरंगे हैं, जिसमें से 171 किमी. का कार्य हो चुका है पूरा

उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्र में जहां ठोस पत्थर नहीं हैं, वहां हिमालयन टनलिंग मैथ्ड से टनल बनाई जा रही हैं, जिसमें टनल बोरिंग के साथ-साथ उसे कंकरीटयुक्त कर मजबूती प्रदान की जाती है, जिससे वह सुरक्षित हो जाती है। इसके अलावा टनल बनाते समय सुरक्षा की दृष्टि से हर काम बहुत सावधानी से करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं।

पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड बजट आवंटन का लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड को 2024-25 के बजट में विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए बजट में 5 हजार 131 करोड़ का आवंटन हुआ है। इस बजट से उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा। श्री वैष्णव ने चार धाम के लिए केंद्र सरकार की अति महत्वकांक्षी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना में 213 किमी. की सुरंगें हैं, जिसमें से अभी 171 किमी. का कार्य पूरा हो चुका है और बाकि का कार्य तेज गति से चल रहा है। रेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना में सुरंगें बनाने के लिए जिन दो टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है उनका नाम 'शिव' और 'शक्ति' रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का कार्य 2026 के मध्य तक पूरा हो जाएगा और ये अपने आप में एक कीर्तिमान होगा कि इतनी बड़ी और जटिल परियोजना को हिमलय के युवा वलित पहाड़ों पर काफी कम समय में पूरा किया जाएगा, जहां कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हिमालय के पहाड़ क्योंकि अभी युवा हैं, इसलिए इसमें अधिकतम मिट्टी पाई जाती है, जो सुरंग बनाने में मुश्किल पैदा करती है। इसलिए हिमालय के पहाड़ों में सुरंग बनाने के लिए हिमालयन टनलिंग मेथ्ड यानी एचटीएम को इजाद किया गया है, जिससे हिमालय के युवा वलित पहाड़ों के भीतर सुरंग बनाई जा सकती है। एचटीएम के माध्यम से संतुलित टनल बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बागेश्वर-टनकपुर, बागेश्वर-गैरसैंण, ऋषिकेश-उत्तरकाशी और सहारनपुर रेलवे लाइनों की डीपीआर बनाने का कार्य जैसे-जैसे पूरा होता रहेगा, इसकी जानकारी साझा की जाएगी।

उत्तराखंड में चल रहे रेल पोजेक्ट्स

उत्तराखंड में 2014 से 2024 तक 69 किमी. के नए रेल ट्रैक बिछे हैं। साथ ही इसी अवधि में 303 किमी. की रेल लाइनों को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। 2009-14 के बीच ये आंकड़ा 0 का था। आज प्रदेश की हर रेलवे लाइन बिजलीयुक्त है। इसके अलावा राज्य में 70 रेल ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण हो चुका है। फिलहाल राज्य में 216 किमी. की 03 रेल परियोजनाओं (रेलवे ट्रैक) का काम चल रहा है, जिसकी लागत 25,941 करोड़ है। साथ ही देहरादून, हरिद्वार जंक्शन, हर्रावाला, काशीपुर जंक्शन, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लाल कुआं जंक्शन, रामनगर, रुड़की और टनकपुर सहित 11 स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा।श्री केदारनाथ धाम के द्वितीय चरण की यात्रा को बेहतर एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए आयुक्त गढ़वाल मंडल ने जीएमवीएन गुप्तकाशी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक की

जयन्त

संस्थापक

स्व.नरेन्द्र उनियाल

प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी

नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित

–सम्पादक

नागेन्द्र उनियाल

आर.एन.आई. 35469/79

फोन/फैक्स 01382–222383

मो. 8445596074, 9412081969

e-mail: nagendra.uniyal@gmail.com